

ffTHE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI K. N. SINGH): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House. (See Appendix XC, Annexure No. 20)]

**F.A.O. Assistance for increasing food production**

\*193. SHRI K. P. SINGH DEO:

SHRI LOKANATH MISRA :  
SHRI JAGBIR SINGH :

Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the U.N. Food and Agricultural Organisation has in a report predicted a serious shortfall in the food production in Asia during 1974-75; and

(b) if so, to what extent India has registered a shortfall in production of essential commodities like rice, whsat, coffee, tobacco, sugar over the corresponding period in 1973-74 and whether any additional assistance is likely to be given by the F.A.O. for increasing the production of these commodities in India ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE): (a) and (b) A statement is laid on the table of the Sabha. [See Appendix XC, Annexure No. 21].

**केन्द्रीय भूमि उपयोग बोर्ड**

194. श्री देवराव पाटिल : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूमि प्रबंध सम्बन्धी समस्याओं पर ध्यान देने के लिये एक उच्चाधिकार प्राप्त केन्द्रीय भूमि उपयोग बोर्ड का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है;

(ग) क्या भूमि के उपयोग सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन को अंतिम रूप दे दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

**'[Centra! Land Utilisation Board**

\*194. SHRI DEORAO PATIL: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether Government have constituted a High-power Central Land Utilisation Board to look into the problems related to land management;

(b) if so, what are the details thereof ;

(c) whether the report of the land use committee has been finalised ; and

(d) if so, what are the main recommendations of the committee ?]

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क)जी नहीं। लेकिन केन्द्रीय भूमि उपयोग आयोग के गठन के प्रस्ताव पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

(ख) ऊपर भाग (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) 12 जुलाई, 1974 को भारत सरकार ने भूमि और मृदा प्रबंध की समस्याओं के समाधान के लिए संस्थागत ढांचे का सुझाव देने के लिए योजना आयोग के सदस्य (कृषि) की अध्यक्षता में एक प्रारम्भिक समिति नियुक्त की। इस समिति ने सितम्बर, 1974 के अन्त में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें केन्द्रीय भूमि उपयोग आयोग स्थापित करने की सिफारिश की गई। सरकार इस प्रारम्भिक समिति की रिपोर्ट पर विचार कर रही है।

(घ) इस प्रारम्भिक समिति की मुख्य सिफारिश यह है कि सरकार को एक केन्द्रीय भूमि उपयोग आयोग स्थापित करना चाहिए, जिसकी जिम्मेदारी भारत की भूमि प्रबंध सम्बन्धी समस्याओं पर लगातार निगाह रखना हो और यह सुनिश्चित करना हो